(b) whether it is a fact that Washington and Paris had turned down India's request for Nuclear Power Plants for the vessel?

THE MINISTER OF DEFENCE (SHRI K.C. PANT): (a) The Concept Design study for the Sea Control Ship is scheduled to be completed by Feb., 1990.

(b) No such request was made to them.

अरावली विकास योजना

*113. श्री मोर्जा इर्शादबेग : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान की अरावली विकास योजना के संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है और इस संबन्ध में आगामी योजनाएं क्या-क्या है ; और

(ख) इस योजना के कब तक पूरा हो जाने की संभावना है ?

योजना मंत्री तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री (श्री माधव सिंह सोलंकी) : (क) योजना आयोग को राजस्थान सरकार से अरावली विकास संबंधी कोई योजना प्राप्त नहीं हुई है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

Import of Computers by the SBI

*114. SHRI M. S. GURUPADASWAMY : Will the PRIME MINISTER be pleased to state :

(a) whether Government have permitted the State Bank of India to order the import of Computors for computerising its twenty-five branches ;

(b) if so, what are the details thereof :

(c) whether the State Bank of India has floated a Rs. 100 crore global tender for this purpose:

(d) whether the State Bank of India, before importing computers from the International Business Machines (IBM), had received offers from the Hindustan Computers (HCL); and

(e) if so, what are the reasons for importing IBM computers ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY AND THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENTS OF OCEAN DEVELOPMENT, ATOMIC ENERGY, ELECTRONICS, AND SPACE (SHRI K. R. NARAYANAN): (a) to (c) The Government have given clearance in principle to State Bank of India (SBI) to procure a suitable computer system through global tendering for their business requirements related to commercial and institutional segments, SBI floated a global tender in September, 1988 for the procurement of this computer system.

(d) and (e) Against SBI global tender, 13 computer vendors have responded which include IBM and HCL. The tenders are under evaluation.

Local people in the Department of Telecommunications in Assam

*115. DR. NAGEN SAIKIA : Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state :

(a) what is the percentage of local people, including Scheduled Castes and Scheduled Tribes in the Telecommunications Department in Assam ;

(b) what was the number of

new appointments made during the last three years; and

(c) the number of local people appointed during the same period ?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI GIRIDHAR GOMANGO) : (a) The percentage of local people, including Scheduled Castes, and Scheduled Tribes in the Telecommunications Department in Assam is 94.2%.

(b) The number of new appointments made during the last three years is 447.

(c) All the 447 employees appointed during the same period are local people.

मध्य प्रदेश में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लोगों की प्रति व्यक्ति आय

*116. **श्री अजीत जोगी :**
ठाकुर जगतपाल सिंह :

क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मध्य प्रदेश के अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लोगों की प्रति व्यक्ति आय के संबंध में कोई आकलन किया है और सामान्य श्रेणियों की तुलना में उनकी स्थिति क्या है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या उस राज्य में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लोगों की प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि करने के लिये सरकार द्वारा कोई पहल की गई है ?

योजना मंत्री तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री (श्री माधव सिंह सोलंकी) : अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रति व्यक्ति आय के अनुमान अलग से उपलब्ध नहीं हैं । मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और समस्त जनसंख्या के औसत मासिक प्रति व्यक्ति खपत व्यय के वर्ष 1983-84 के लिए अनुमान उपलब्ध हैं जो नीचे सारणी में दर्शाए गए हैं :—

(रुपए)

वर्ग	ग्रामीण	शहरी
अनुसूचित जाति	72.70	93.46
अनुसूचित जनजाति	65.64	112.85
समस्त जनसंख्या	92.82	137.02

सरकार ने अभावग्रस्त समूहों के लोगों के लिए परिसम्पत्तियों, दस्तकारी और रोजगार की व्यवस्था के जरिए विकास और गरीबी उन्मूलन के सामान्य कार्यक्रमों के अलावा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों की विशेष रूप से आर्थिक दशा सुधारने के लिए अनेक उपाय किए हैं। अनुसूचित जनजाति के लोगों के विकास के लिए जनजाति उपयोजनाएं और अनुसूचित जाति के लोगों के लिए विशेष संघटक योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं। जनजाति उपयोजना और विशेष संघटक योजना का उद्देश्य अलग अलग लाभभोगी परिवार के लिए सेवाओं के पैकेज की इस प्रकार से व्यवस्था करना है कि उनकी विशिष्ट आय